झारखण्ड सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत तृतीय झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र में झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल

श्री के० शंकरानारायणन

का

अभिभाषण

राँची, 8 जनवरी, 2010

झारखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के प्रथम सत्र में आप सभी को सम्बोधित करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि तृतीय विधान सभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। मैं आशा करता हूँ कि सभी निर्वाचित विधायक झारखण्ड के चहुँमुखी विकास से सम्बन्धित मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखकर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही माननीय सदस्यों और झारखण्ड के निवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएँ देता हूँ।

2. लोकतंत्र का यह मूलमंत्र है कि लोगों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। झारखण्ड की जनता ने लोकतांत्रिक ढंग से अपने विवेक का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधियों को चुना है। राज्य में नई सरकार का गठन प्रदेश को सकारात्मक नेतृत्व तथा राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और ऐसा वातावरण पैदा करने में सफल होगी जो प्रदेश में विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि समाज का हर वर्ग राज्य की विकास की प्रक्रिया से समान रूप से जुड़े और हम सबकी सम्मिलित सृजनात्मक ऊर्जा इस राज्य के उत्थान के प्रति समर्पित हो। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार झारखण्ड राज्य की सम्पूर्ण जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए निष्पक्ष नीतियों पर चलेगी।

3. राज्य के चतुर्दिक विकास की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूरी सजगता एवं चौकसी के साथ कार्य करेगी और स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करेगी। सरकार विकास के संकल्प पर काम करेगी ताकि राज्यवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप भय, भूख तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

Hon'ble Speaker and the Members of Jharkhand Vidhan Sabha

1. I feel extremely happy to address this very first session of the third Jharkhand Vidhan Sabha. It's heartening that the General Elections for the third Jharkhand Vidhan Sabha in the State could be conducted peacefully. I hope that all the Elected Legislators would emphatically raise issues pertaining to the alround development of the State and would extend their active cooperation in the developmental process. On this occasion, I welcome and felicitate the Hon'ble Members of the Vidhan Sabha. I also offer my heartiest greetings to the honourable members of the House and all the people of the State for a very happy and prosperous new year.

2. It is the spirit of the democracy that the present and the future path of the people is guided and facilitated by their elected representatives. The people of Jharkhand have elected their representatives in a democratic way and I congratulate them for doing so. The new government in the State would provide constructive leadership to the State with political stability. I am of the firm belief that my Government will come upto the expectations of the people and would be able to create an atmosphere that would lead the State to the path of development and progress. My Government will make all efforts to see that every section of the society becomes a part of the process of development with equity and our creative synergy contributes to the upliftment of the State. My Government will keep the interests of all sections of the people in mind in determining its priorities.

3. To fulfil the commitment of alround development of the State as per the established norms , my government would work with care and promptness and provide a clean, transparent and sensitive administration. My Government will work with the commitment to meet the expectations of the people to provide them a society free from fear, hunger and exploitation.

4. राज्य में अपराधमुक्त, भयमुक्त तथा अन्यायमुक्त समाज का निर्माण करना हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा। समाज के वैसे वर्ग जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का शिकार रहें हैं, विशेष कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों को विकास की नीति के निर्धारण में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य में जाति, धर्म एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के हितों का समुचित ध्यान रखा जायेगा।

5. हमारी सरकार लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित एवं समेकित विकास के लिए वचनबद्ध है। मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनायेगी। राज्य के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार कदापि क्षम्य नहीं होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा जिससे कि वे अपने दायित्वों को प्रभावकारी रूप से निष्पादित कर सकें।

6. राज्य में विकास के चक्र को अंतिम गाँव और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार ने अपनी प्राथमिकतायें स्पष्ट करते हुए यह निर्णय लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों का पुनः सर्वेक्षण करवाकर छूटे हुए सभी योग्यताधारी परिवारों को बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित करवाया जाए एवं उन्हें बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की ढिलाई एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी परिवारों को कालबद्ध रूप से राशन कार्ड उपलब्ध करवाये जायें। लोगों को पंचायत स्तर पर ही प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की जायेगी। अगले 100 दिनों में राज्य में ऐसे 500 प्रज्ञा केन्द्रों से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आरम्भ कर दिया जायेगा।

7. वर्तमान में राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 34 किलोग्राम

4. It would be the objective of my Government to create a social environment free from crime, fear and injustice. The Government, would keep the interests of the people, who have been the victims of social and economic inequalities for a long time particularly the Schedule Castes, Schedule Tribes, the downtrodden, the backwards and the minorities, at the top of the priorities while drawing the developmental road map. However, the interests of all the classes of the societies will be taken care irrespective of caste, religion and party-politics.

5. My Government is committed to the equitable and holistic development keeping the public interest at the top. I emphasise that my Government will adopt the policy of zero tolerance towards corruption. Corruption would not be tolerated in any way in the State. The vigilance system will further be strengthened so that it can function in a more effective way.

6. My Government has clearly defined its priorities to take the benefits of development to the last person in the last village. It has been decided that a fresh survey of the people living below poverty line would be conducted and all the eligible families will be included into the BPL list and will be provided the BPL cards and no slackness will be tolerated in execution of this work. The State Government would also ensure that all the people in the State do get the Ration Cards within a fixed time frame. Concrete actions would be taken so that people do get the birth and death certificates at the Panchayat level through Pragya Centres. Availability of birth and death certificates from 500 such Pragya Centres would be ensured within next 100 days.

7. The State Government at present is providing 34 kilogram of food grains per month per BPL family and 35 kilogram food grains per month per Antyodaya family free of cost to help them to cope up with the drought situation in the State. The Government will continue the scheme of distribution of free grains to BPL and Antyodaya families in the remaining

चावल एवं अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए भी जारी रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के आवश्यकता आधारित गरीब परिवारों को अनुग्रह अनुदान (GR) के रूप में उपलब्ध कराई जा रही रु0 400.00 प्रति माह की राशि भी इस वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती रहेगी। अगले वित्तीय वर्ष से हमारी सरकार गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को कम–से–कम मूल्य पर प्रति माह प्रति परिवार 35 किलो अनाज एवं आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

8. राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत देय राशि की बढ़ोत्तरी किये जाने पर गंभीरता से विचार करेगी।

9. राज्य सरकार की यह स्पष्ट सोच है कि जबतक सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में पर्याप्त रूप में मानव संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, तब तक राज्य में विकासात्मक कार्यक्रमों को आशातीत गति नहीं दी जा सकेगी। इस हेतु जिला एवं सभी अन्य स्तरों पर उपलब्ध रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी, जिससे विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ समयबद्ध रूप से आम जनता तक पहुँचाया जा सके।

10. झारखण्ड राज्य एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसकी 70–80 प्रतिशत आबादी अभी भी जीविका हेतु कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी एवं इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर करती है। यद्यपि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79 लाख हेक्टेयर में से 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, परन्तु फिर भी सुनिश्चित सिंचाई की सुविधाओं के अभाव में हम खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। मेरी सरकार राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सिंचाई के साधनों का विकास करेगी एवं इंटिग्रेटेड फार्मिंग योजना का विस्तारीकरण किया जायेगा। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तथा कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। सिंचाई हेतु चेक डैम तथा तालाब की योजनाओं का कार्यान्वयन

part of current financial year. Besides this the needy poor families would continue to get the Gratuitous Relief of Rs 400 per family per month also during the remaining period of the current financial year. My Government would ensure to make available 35 kilograms of food grains and iodised edible salt to the BPL families at the minimum possible rate from the coming financial year.

8. The Government would also review the amount being given under the Old age Pension Scheme and would consider its augmentation.

9. It is the firm belief of Government that the developmental programmes in the State cannot be implemented at expected pace until sufficient personnel are made available to all the Government Departments and Agencies. To ensure this expeditious appointments would be made to the available vacant posts at district as well as all other levels, so that the benefits of ongoing schemes and programmes can percolate to the people in stipulated time.

10. Jharkhand is a rural economy where 70 to 80 percent population still depends on agriculture, animal husbandry, fisheries, forestry and related sectors for their livelihood. The State, though, has 38 lakh hectare of agricultural land out of its total geographical area of 79 lakh hectares but mainly due to the lack of assured irrigational facilities we are not self-sufficient in the production of food grains. My Government would expedite development of irrigation facilities as per the topographic condition of the State and implement the Integrated Farming Scheme with greater vigour and extend it to the uncovered areas. It would increase the productivity of agriculture and would also augment the income of farmers. The schemes of Ponds and Check Dams would be executed at priority level for irrigation. Under National Agriculture Development scheme major emphasis would be given upon creation of water sources viz. Birsa Pucca Check Dams, Loose Boulder Check Dam and micro irrigation and on better use of irrigation facilities.

प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मुख्यतः जलस्रोत के निर्माण यथा बिरसा पक्का चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम एवं सूक्ष्म सिंचाई तथा उपलब्ध जल संरचनाओं के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जायगा।

11. दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के विगत दो वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन एवं कृषि के अन्य क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जैसे राज्य की बीज प्रतिस्थापन दर वर्तमान में 25 प्रतिशत तक हो गयी है, जो कि राज्य गठन के समय मात्र 4–5 प्रतिशत ही थी। इसे 33 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में फसल आच्छादन, उत्पादकता एवं फसल सघनता में भी बढ़ोतरी करने का भरपूर प्रयास किया जायेगा।

12. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् लैम्प्स एवं पैक्स, जिला केन्द्रीय बैंक एवं अन्य व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से खरीफ, 2008 में बीमित फसलों के लिए लगभग 26.00 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्त्ति राशि की स्वीकृति दी गई है। चालू वर्ष 2009 में खरीफ के लिए 1000.00 करोड़ रुपये का फसल बीमा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है, जिसके लिए किसानों द्वारा लगभग 26.00 करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया गया है। सरकार द्वारा पूरे राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित किए जाने के आलोक में किसानों द्वारा जमा किए गए उक्त प्रीमियम की राशि, किसानों को प्रतिपूर्त्ति करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

13. राज्य सरकार झारखण्ड के चतुर्दिक एवं सर्वांगीण विकास को सतत् रूप से गतिमान रखने हेतु प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास तथा कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए ताकि उपलब्ध राशि का उचित उपयोग हो सके। इस हेतु राज्य सरकार अगले 100 दिनों में किये जाने वाले कार्यों को लक्ष्यबद्ध करते हुए उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य करेगी। चालू वित्तीय वर्ष में सम्पन्न

11. The State has witnessed the progressive improvement in the food production and other areas of agriculture during the first two years of the eleventh five year plan in comparison to the tenth plan. The Seed replacement ratio that was merely four to five percent at the time of formation of the State has now been brought up to twenty five percent at present. The State aims to further increase it to thirty three percent. The Government would make all the efforts to improve the agricultural crop coverage, intensity and productivity in remaining period of the eleventh five year plan.

12. An amount of Rs. twenty six crore as compensation money has been sanctioned to be disbursed through LAMPS, PACS, District Central Banks and other Commercial Banks as compensation for the crops insured during Kharif, 2008 season under the National Crop Insurance Scheme. Agriculture Insurance Company of India has insured crops during Kharif, 2009 season worth Rs. one thousand crore for which the farmers have paid Rs. twenty six crore as premium. The Government has taken a decision to reimburse the total premium cost to the farmers in view of the drought situation prevailing in the State.

13. My Government is fully committed to make all the efforts to expedite various schemes and programmes for alround holistic development of the State. The implementation of different programmes and schemes will be streamlined to ensure full utilization of the available funds. The Government, for this purpose, would clearly identify the targets to be achieved in the next 100 days and would work in a very focussed way to implement the schemes at the ground level. Though there has been some delay in the implementation of the many schemes due to the repeated imposition of model code of conduct because of the General Elections to the Parliament and State Vidhan Sabha, but my Government is firm in its view that the pending schemes can be completed and their benefits can accrue to the people if a clear prioritised programme for

लोकसभा एवं विधान सभा के आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ विलम्ब हुआ है, तथापि हमारी सरकार की यह सोच है कि इस वित्तीय वर्ष के शेष दिनों में कार्य योजना निर्धारित कर विलम्बित योजनाओं को पूर्ण कर इनका लाभ जन–जन तक पहुँचाया जाए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कर्णांकित राशि में से अधिक–से–अधिक राशि राज्य को उपलब्ध हो सके।

14. राज्य में दुग्ध उत्पादन लगभग 44 लाख लीटर प्रतिदिन है। राज्य की आवश्यकता की पूर्त्ति हेतु वर्ष 2020 तक 75 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेण्ट बोर्ड के नियंत्रण में संचालित "झारखण्ड डेयरी प्रोजेक्ट" अन्तर्गत राँची जिला में एक लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता की डेयरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। 25 हजार लीटर क्षमता तथा 10 हजार लीटर क्षमता की दो डेयरी स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी कम से कम एक डेयरी स्थापित करने की कार्रवाई की जायेगी।

15. हमारी सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के गरीब नागरिकों को स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाकर राज्य की ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में सतत् प्रयास करेगी। सहकारिता, विकास का एक सशक्त माध्यम है, जो परस्पर सहयोग पर आधारित एक जन आंदोलन है, जिसके मूल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावना अंतर्निहित है।

16. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाएँ हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमें उनके आर्थिक विकास की दिशा में ठोस पहल करनी होगी। अभी तक राज्य में महिलाओं के 32,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सीड मनी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की गई है। हमारा प्रयास होगा कि शेष ग्रामीण महिलाओं को भी स्वयंसहायता समूह के रूप

the next 100 days is drawn and implemented in a result oriented way. The Government would also ensure that it gets the maximum amount of the Central funds and will strive for its optimal utilization.

14. Milk production in the State is forty four lakh litres per day. To be sufficient in the milk production target has been fixed for increasing the milk production capacity to seventy five lakh litres per day by 2020. The work on the establishment of a dairy of capacity of one lakh litres per day in Ranchi under the Jharkhand Dairy Project, being run under the control of National Dairy Development Board, is in progress. The establishment of dairy of the capacity of twenty five thousand litres per day and another dairy of capacity of ten thousand litres per day are under process.

15. Co-operatives have been very powerful means of development which are based on a public movement having the concept of social and economic development through collective efforts and co-operation among the people. My Government is making all efforts to develop the rural economy of the State by making the poor people self reliant, self supporting and economically prosperous through the co-operative societies.

16. It would not be an exaggeration to say that the women are back bone of rural economy. We will have to take sincere effort in the direction of their economic upliftment. Up till now thirty two thousand self help group of the women in the State have been constituted and seed money was made available to them. It would be our effort to organise rest of women in form of self help groups, so that they can stand as strong pillar in our economy.

17. Our Government is committed to provide the employment opportunities right in the villages and check the out migration of the labourers. For this purpose more and more schemes would be taken up and executed in all the panchayats of the State under NREGA and the opportunities

में संगठित कर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तम्भ के रूप में खड़ा किया जाए।

17. हमारी सरकार गाँवों में ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर मजदूरों का पलायन रोकने के लिए कटिबद्ध है। इस हेतु नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अधिक–से–अधिक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किये जायेंगे। नरेगा में बिचौलियों की भूमिका के बारे में समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। मजदूरों का हक छीनने का प्रयास करने वाले वैसे बिचौलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जायेगा।

18. झारखण्ड की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा असंगठित मजदूर के रूप में कार्य कर अपनी जीविकोपार्जन करता है। वैसे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। मजदूरी की दरों में भी आवश्यकतानुसार बढ़ोत्तरी की जायेगी।

19. राज्य में उद्योगों एवं आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है, जिससे विस्थापन की समस्या खड़ी होती है। हमें विस्थापितों की पीड़ा को समझना होगा। राज्य की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की समीक्षा कर इसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए और अधिक हितकारी बनाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार की यह एक प्रमुख प्राथमिकता होगी कि उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण को ग्रामीणों के हित में और अधिक लाभकारी बनाया जाए। इससे एक ओर राज्य में उद्योगों एवं आधारभूत संरचना की स्थापना को बल मिलेगा, साथ ही विस्थापितों के हितों की भी रक्षा की जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेने की दिशा में भी ठोस पहल की जायेगी।

20. राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन ससमय कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। इस योजना के तहत गाँवों का विद्युतीकरण कर गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा। अभी तक 19737 गाँवों के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 9798 गाँवों का

of employment will be created at the local level itself. Often complaints are received about exploitations by intermediaries in NREGA. Severe action would be taken against those intermediaries who are involved in exploiting the labourers.

18. A big chunk of rural as well as urban population of Jharkhand earns their livelihood as unorganised labourers. The laws meant for protecting interest of such labourers would be implemented firmly. The rate of wages for such labourers would be enhanced as per minimum needs.

19. The imperative to acquire the lands of villagers for establishment of infrastructure and industries in the state, that leads to the problem of displacement. We have to understand the suffering of the displaced persons. The Resettlement and Rehabilitation Policy needs a review to make it more favourable for the displaced persons. It would be the prime priority of our Government to put in place a revised Rehabilitation Policy that ensures justice to the displaced persons. It would enable the establishment of infrastructure and industries on one hand and the interest of displaced persons would also be protected. Sincere effort would be made for seeking the cooperation of villagers in land acquisition process.

20. Necessary steps would be taken for timely execution of Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme. Free electric connections would be given to the villagers living below poverty line. Up till now only 9798 villages have been electrified against the target of 19737 villages. All the possible steps would be taken to increase the pace of execution of the scheme.

21. My Govt. is committed to provide education, health, safe drinking water and other civic amenities to every citizen of the State to improve their standard of living.

22. Primary Education is now a Fundamental Right. To fulfil this constitutional obligation, my Govt. promises to take all steps to ensure that every child in Jharkhand gets primary education. To upgrade &

ही विद्युतीकरण हो सका है। इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

21. हमारी सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य नागरीय सुविधायें सहज रूप से उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन–स्तर में उत्थान लाने हेतु प्रतिबद्ध है।

22. प्रारंभिक शिक्षा को अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। मेरी सरकार इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूर्ण करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठायेगी और सुनिश्चित करेगी कि राज्य का कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विकास हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में दो मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जायेगा। 203 शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में से प्रत्येक में मॉडल विद्यालय की स्थापना की जायेगी। उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधायें सृजित करने हेतु राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में नये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पोलिटेकनिक, आई0टी0आई0 तथा पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की दिशा में भी कार्रवाई की जायेगी।

23. राज्य में छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वभौमिक विकास हेतु समेकित बाल विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के लिए पूरक पोषाहार की व्यवस्था की जाती है, 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है एवं 3–6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों से समेकित बाल विकास योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।

improve the qualitative status of Secondary Education in the State, at least 2 middle schools shall be upgraded to Secondary Schools in each block of the State. Model schools shall be opened in 203 educationally backward blocks of the State. Establishment of the girls' hostels in the Kasturba Gandhi Residential Girls Schools shall be taken up on priority basis. To upgrade the standards of higher education in the State, a Central University has been established in the State and steps shall be taken for opening the National Law College and Indian Institute of Management. It is of utmost importance to modernize and update the infrastructural facilities as well as to update the course curriculum of the higher education in the State so as to provide our students with a competitive and contemporary education. My Government shall give due priority to educational infrastructure development in a time bound manner.

23. The Integrated Child Development Scheme (ICDS) Programme is on the top of the agenda for overall development of the children up to the age of six years and has been running successfully in the State since the last couple of years. Under this flagship Programme, children from the age of 6 months to 6 years, pregnant women, lactating mothers and adolescent girls are provided micronutrient enriched food as well as immunization as per their requirement, for overall development and improvement of the health indices. Strengthening of the pre-schooling component for the children in the age group of 3-6 years in Aanganwadis for ensuring higher retention in the primary school level will be the priority of the Government. The primary focus of the Government shall be to strengthen and support the Aanganwadi Kendras in the State which are the hub of the ICDS activities.

24. My Government shall also ensure that the Vivekanda Nishakt Swavlamban Protsahan Yojana, Handicap Scholarship Yojana and the programme for providing special equipments to the handicapped persons shall be implemented in a transparent way so that the disabled

24. राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना, विकलांग छात्रवृत्ति योजना एवं विकलांगों के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराने की योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए, जिससे निःशक्तजन इनका पूर्ण लाभ उठा सकें एवं राज्य एवं समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। राज्य की गरीब लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलायी जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी मेरी सरकार इस प्रकार कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी कि राज्य की अधिक–से–अधिक बेटियों को इसका लाभ मिल सके। राज्य में प्रचलित डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा सामाजिक जागरूकता पैदा करने एवं ग्रामीण स्तर पर लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम भी चलाया जायेगा।

25. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कटिबद्ध है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में भी सकारात्मक कार्रवाई की जायेगी। आदिम जनजातियों के परिवारों के लिए प्रति माह 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न देने हेतु मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना एवं आदिम जनजातियों के बसाव एवं उनके प्रवास के लिए बिरसा मुण्डा आवास योजना को न केवल जारी रखा जायेगा, बल्कि इनके लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा। हमारी सरकार की यह एक प्रमुख प्राथमिकता होगी कि राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने हेतु इसके प्रावधानों का वृहत् रूप से प्रचार–प्रसार करवाया जाए तथा योग्यताधारी लोगों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाए।

26. झारखण्ड सरकार राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। स्वस्थ झारखण्ड–सुखी झारखण्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर से

people are able to take full advantage from programmes being executed for them and thus enable them to live a complete life and also bring them in the mainstream of the development. The Mukhya Mantri Kanyadaan Yojana being implemented to supplement the marriage expenditure of the poor girls, will be executed in such a manner so that more and more girls of our state would get its benefit. A social awareness programme shall also be implemented in the State to eradicate the social evil of witchcraft and a programme to educate the rural people about this issue would also be initiated.

25. My Government is pledged to reach to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Primitive Tribes, Backward class through the various programmes executed for the socio-economic and educational development of these weaker sections of the society by giving thrust on inclusive growth & development strategy with a focus on bringing these sections in the mainstream of development. Positive action would be initiated for educational, social and economic upliftment of minority community. The ongoing programme of Mukhyamantri Khadya Suraksha Yojana which provides 35 kilogram of free food grains to the families of the Primitive Tribes and the Birsa Munda Awas Yojana which provides dwelling facilities for the Primitive Tribes shall not only be continued but also the targets shall be achieved in the given time frame. One of the prime focus of this Government would be the effective implementation of the Forest Rights Act, 2006.This needs massive awareness generation amongst the masses to access the facilities which can be possible only through rigorous mass campaign in terms of Information, Education and Communication through various media activities.

26. The Government of Jharkhand is committed to attain its dream of making quality health care services accessible to the people residing in the far flung hard-to-reach areas. In order to achieve the goal of 'Healthy

ग्राम स्तर तक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण एवं उनको पर्याप्त चिकित्सकों, पारा–चिकित्सा कर्मियों, नर्सों आदि एवं चिकित्सीय उपकरणों एवं सामग्रियों से सुसज्जित करने की नितान्त आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार प्राथमिकता से पूर्ण करेगी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों तक पहुँचायेगी, जिससे राज्य के स्वास्थ्य सूचकांकों में सार्थक एवं गुणात्मक परिवर्त्तन लाया जा सके। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन तेजी से किया जायेगा। ए0एन0एम0 तथा नर्सो के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जायेगा ताकि ग्रामीण महिलाओं को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

27. राज्य सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन एवं मलिन बस्ती (स्लम) विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देकर बेरोजगारी एवं कुपोषण दूर करने का कार्य करेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्व–नियोजन को बढ़ावा देगी। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिफॉर्म मिशन के अन्तर्गत राज्य में स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सम्पूर्ण स्वच्छता, सिवरेज ड्रेनेज सिस्टम एवं शहरी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम को कार्यान्वित किया जायेगा।

28. सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र अन्तर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जमीनी स्तर पर बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठाये जायेंगे।

29. हमारी सरकार राज्य में उद्योगों की स्थापना करते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजन का प्रयास करेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नयी औद्योगिक नीति का गठन शीघ्र किया जायेगा। झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति–2008 को विस्थापितों के हित में और लाभकारी बनाने की कार्रवाई

Jharkhand, Happy Jharkhand', emphasis shall be laid on the institutional strengthening right from the State level to the village level. The gaps in terms of trained manpower, inadequate infrastructure, quality services and the required resources shall be covered primarily to make the health services accessible, available and affordable to each and every single citizen of the State. The execution of National Rural Health Mission would be accelerated. The vacant posts of ANMs and Nurses would be filled on priority basis so that quality health services could be accorded to rural women.

27. The State Government shall execute the Urban Poverty Eradication & Slum Development Programmes to minimize the burden of unemployment and malnourishment by emphasizing on the health, education and self employment agenda in the urban areas. Under the aegis of the Jawaharlal Nehru Urban Reform Mission, thrust shall be to improve and increase the availability of safe drinking water, total sanitation, sewerage & drainage system and urban waste disposal system to develop the civic facilities in the urban areas.

28. Measures would be taken for ensuring better ground level execution of various programmes under the Social Security Schemes viz. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Handicap Pension Scheme, State Social Security Pension Scheme, National Family Pension Scheme, Rehabilitation Programme for the Bonded Labour, Public Provident Fund, National Family Health Yojana, and Employees State Provident Fund Scheme. The Government shall ensure the efficient implementation of all of these schemes for the benefit of the target groups.

29. Our government shall give thrust and create a conducive environment for labour intensive industrialization to enhance employment opportunities in the State. To motivate and trigger off the industrialization process, a new Industrial Policy shall be formulated very

की जायेगी। अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से रेशम एवं रेशम से जुड़े उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

30. अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण झारखण्ड राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है और उसके संवर्द्धन के लिए "झारखण्ड पर्यटन नीति", "झारखण्ड पर्यटन प्रोत्साहन भूमि नीति" एवं "झारखण्ड पर्यटन गृह आवासन योजना" को अन्तिम रूप दिया जायेगा। प्रत्येक जिले में पर्यटकों हेतु रेस्तराँ, पर्यटक सूचना केन्द्र, हस्तकला विपणन केन्द्र, शौचालय, आवासन सुविधाएँ, ए0टी0एम0 काउण्टर आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी।

31. राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। ग्रामीण संपर्क पथ आधारभूत संरचनाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी तक राज्य में लगभग 1000 करोड़ रुपए के व्यय से लगभग 4000 कि०मी० पथों का निर्माण कर 1825 आबादियों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। लगभग 5200 कि०मी० सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे 4000 अतिरिक्त बसावटों को जोड़ा जा सकेगा। इन अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने की कार्रवाई की जायेगी।

32. भारत सरकार के द्वारा मार्च, 2011 तक भारत निर्माण योजना के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु युद्धस्तर पर प्रयास किया जायेगा। लगभग 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है, जिसके द्वारा 2250 कि०मी० पथों का निर्माण कर लगभग 1400 बसावटों को जोड़ा जा सकेगा। भारत सरकार से इस योजना पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जायेगी।

33. किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए उन्नत पथ यातायात व्यवस्था परमावश्यक है। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पथ यातायात व्यवस्था एवं सुदृढ़ीकरण इसके विकास के लिए नितांत आवश्यक है। गाँवों को

soon. Rehabilitation Policy, 2008 is already in place in the State which may be revised suitably. In order to increase employment generation, priority is being accorded for the expansion and development of the silk and lac related industries.

30. Jharkhand has been bestowed with incredible natural beauty and exotic geographic locations which have prompted the State to declare tourism as an industry in the State. To rope in the benefits of a full fledged tourism industry, the Jharkhand Tourism Policy, Jharkhand Paryatan Protsahan Bhumi Niti and Jharkhand Paryatan Awashan Yojna would be finalised soon. The adequate action will be taken in every District for providing infrastructural facilities such as information centres, restaurants, cottage and handloom emporiums, boarding and lodging amenities and ATM counters etc. for tourists.

31. It would be the priority of the Government to create the required infrastructure in the rural area to ensure the economic development of the state. Rural approach Roads are one of the main link in the infrastructure. Till now 4000 Km of approach roads have been constructed to provide accessibility to 1825 habitations and the work is in progress to construct another 5200 Km of approach roads to provide access to additional 4000 habitations. These left over work will be completed on priority basis.

32. The State Government would make all efforts at war footing to achieve the targets of Bharat Nirman Yojna as determined by Government of India by March, 2011. The proposal for 600 crore rupees has been sent to Government of India which would provide for the construction of 2250 kilometers of roads to link about 1400 additional habitations. Concrete step would be taken to expeditiously obtain concurrence of the Government of India on these proposals.

33. Improved road communication is the most essential ingredient for development of any region. The geographical condition of the State of

प्रखण्ड मुख्यालय तथा प्रखण्ड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा जायेगा। राजधानी राँची तथा विभिन्न जिला मुख्यालयों के बीच उपलब्ध पक्की सड़कों का चौड़ीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। राज्य गठन के पश्चात् अब तक लगभग 1600 करोड़ की लागत से लगभग 3850 कि0मी0 पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एवं 65 पुल योजनाओं का निर्माण सम्पन्न किया गया है। राज्य में 15 आर0ओ0बी0 का निर्माण राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय के संयुक्त निधि से रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कुल 12 आर0ओ0बी0 का निर्माण पूर्ण किया गया है, शेष आर0ओ0बी0 कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

34. राज्य में कुल 23605 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत है। राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत अबतक 10,900 ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है, जो लगभग 20.00 लाख हेक्टेयर वनक्षेत्र में सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। झारखण्ड में विभिन्न लघु वन पदार्थों यथा लाह एवं तसर के उत्पादन की अपार क्षमता है। राज्य में उत्पादित, संग्रहित लघु वन पदार्थों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु प्राथमिक उत्पादकों, संग्रहणकर्त्ताओं के स्वयं सहायता समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण और आरंभिक उपकरणादि उपलब्ध करायी जायेगी। ग्रामीण आय में वृद्धि के इन प्रयासों को राज्य में प्राथमिक उत्पादकों, संग्रहणकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लागू किये जानेवाले लघु वन पदार्थों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था एवं झामकोफेड, वन निगम के माध्यम से वैकल्पिक विपणन् की व्यवस्था से मदद मिलेगी।

35. झारखण्ड राज्य 34वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजित कर रहा है। इस हेतु राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना बनकर तैयार है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य रूप से आयोजन निकट भविष्य में हो। राज्य में खेल अकादमी के गठन की कार्रवाई की जायेगी। प्रत्येक जिला तथा प्रखण्ड मुख्यालय में कम से कम एक खेल स्टेडियम

Jharkhand is such that the road communication system and its strengthening are the most essential for its development. All villages would be linked to the block head quarters and the block head quarters to the district head quarters by concrete roads. Concrete roads between different districts head quarters and State capital Ranchi would be widened in phased manner. Since the creation of State the widening and strengthening of about 3850 KMs of Road and constructions of 65 Bridges has been completed at the cost of Rs. 1600 crores. The construction of 15 Railway over bridges has been undertaken under joint venture of the State Government and the Railway Ministry. The construction of 12 Railway over bridges has been completed and the work on the rest of the three is likely to be completed very soon.

34. The State has twenty three thousand six hundred five square kilometer area under forests which constitutes 29.61 percent of the total geographical area of the State. With the concept of Joint Forest Management, 10900 Village Forest management and protection committees have been constituted in the State till now which are engaged and involved in the protection of forest area spread over 20 lakh heactare in the State. Jharkhand State has immense economic opportunities as far as the minor forest produce are concerned. The Self Help Groups of the primary producers and collectors would also be trained and provided with necessary materials to give an impetus for the processing of the minor forest produce. The Minimum Support Price structure for the minor forest produce and the alternative marketing arrangements are facilitated through State Forest Development Corporation and Jharkhand State Minor Forest Produce Co-operative Development and Marketing Federation aimed at protecting the interests of the primary producers and collectors and this would synergise the efforts of the Government to enhance the rural economy.

35. Our State is going to organise the 34th National Games. The sports infrastructure meeting the International Standards is ready for this

के निर्माण की योजना चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत की जायेगी।

36. हमारी सरकार राज्य में प्रशासन को पारदर्शी, संवेदनशील एवं लोकप्रतिबद्ध बनाने के लिए कृतसंकल्प है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना हमारा लक्ष्य है। राज्य कर्मियों को उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित पदाधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे। जन शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर आपत्ति निराकरण सेल की स्थापना की जायेगी ताकि जनता की शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा के अन्दर हो सके। राज्य सरकार के कर्मियों तथा पदाधिकारियों द्वारा जवाबदेही में किसी प्रकार की कोताही तथा लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। गैरजिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मियों के विरूद्ध त्वरित न्यायसंगत प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। राज्य के पुलिस तंत्र को जन आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किया जायेगा।

37. हम सब अवगत हैं कि झारखण्ड को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए समय–समय पर आन्दोलन चलाये गये थे। वैसे आन्दोलनकारियों की कुर्बानी का हम सम्मान करते हैं। उनके विरूद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई तो की ही जायेगी, साथ ही साथ उन्हें सम्मान पेंशन भी स्वीकृत की जायेगी।

38. हमारी सरकार की यह अवधारणा है कि नक्सलवाद की समस्या का हल जनता के प्रति उत्तरदायी प्रशासन एवं कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर कार्यान्वयन करने तथा मुख्यधारा से भटके युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने से ही संभव है। सरकार ऐसे सभी भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास करेगी।

39. अंत में, मैं आप सब को पुनः बधाई देना चाहूँगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाये रखेंगे और आपके विचार–विमर्श में सदैव निःस्वार्थ सेवा, अपने

purpose. Our Government would ensure that the National Games are successfully organised in grand way in near future. State Sport Academy would be constituted soon and scheme of construction of Sport Stadium in each district and block head quarter would be implemented in phased manner.

36. My Government is committed to provide a fully transparent, sensitive and public oriented administration. Our goal is to establish a system of administration absolutely free from corruption. Public Servants would be made fully accountable for their duties and the concerned officials would be fully responsible for the successful and timely implementation of the different developmental programs and schemes. A Complaint Redressal Cell would be constituted at all the administrative levels to redress the grievances of the people within the stipulated time frame. No slackness and dereliction of duty by State personnel and officers would be tolerated. Necessary administrative action would be taken against irresponsible officers and personnel. An effective effort would be initiated for making the Police system sensitive to the expectation of the people.

37. We all are aware that many agitations were organised for the creation of Jharkhand. We honour the dedication of those activists. Steps would be taken to withdraw the cases against them and also award honour pension to them.

38. My Government is of the view that the solution of the naxal problem in the state lies in providing a responsive and accountable administration to the people and implementation of the development and welfare schemes at the ground level and also bringing back the alienated youths into the mainstream of development. My Government calls upon all such alienated youths to give up violence and join the mainstream and contribute in the development of the society and the State.

सार्वजनिक कर्त्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं जनता का हित ही प्रमुख होगा। झारखण्ड के इस सबसे बड़े पंचायत में आप सभी मिलकर एक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखण्ड के निर्माण के लिए प्रयत्नशील होंगे।

जय झारखण्ड ! जय हिन्द !

39. Before I conclude my address again I would like to congratulate all the Hon'ble Members. I am fully confident that Hon'ble Members will always maintain the high traditions and sanctity of this House. I earnestly hope that selfless service and commitment to the larger public interest would always be paramount in your discussions in this house. I do hope through this highest Panchayat of the State you all will always collectively make efforts to make Jharkhand a prosperous and developed State.

Jai Jharkhand Jai Hind